



2026:AHC:50022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट -सी संख्या -9136 वर्ष 2026

बीना श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शांति धर द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रदीप सिंह

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

- याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
- इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2, यानी नायब तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला मिर्जापुर को निर्देश दिया जाए कि वे केस आरएसटी संख्या 1781/2024 (कम्प्यूटरीकृत केस संख्या टी202416530201781), (बंदना श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत दायर रिकॉल आवेदन पर, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लें।
- याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यू.पी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का निपटारा एक समय-सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

WRIC सं. 9136 वर्ष 2026

2

“(7) तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के निर्विवाद प्रकरण का निस्तारण वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथा विवादित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण 90 दिवस की अवधि के भीतर कर दिया जाए; और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसके कारणों का अभिलेखन किया जाएगा।”

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है, तथापि आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है; अतः यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2, नायब तहसीलदार, तहसील लालगंज, जिला मिर्ज़ापुर को यह निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त मामले का निर्णय यूपी. राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, बशर्ते कि इसमें कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,)

11 मार्च, 2026

स्वाति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।